वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मई, 2024 माह हेतु मासिक उपलब्धियां
*****

1. कैपेक्स लक्ष्य:

मई, 2024 तक चुनिंदा सीपीएसईज़ (वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य ₹100 करोड़ और उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 05.06.2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 7.76 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) के अनुमानित व्यय के मुकाबले, उपलब्धि **0.96 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात् दिनांक 31.05.2024 तक लगभग 12.35% है।**

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

i. आरडीसी योजना के तहत वर्ष 2024-25 (क्यू 1 और क्यू 2) के लिए सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया।

ii. दिनांक 20 मई, 2024 को डीपीई ने सीपीएसईज़ के मौजूदा वर्गीकरण के उन्नयन के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

iii. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) को नवरत्न का दर्जा देने के रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक दिनांक 9 मई, 2024 को आयोजित की गई थी।

3. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 90 सीपीएसईज़ में से 10 के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापनों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई।

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल टिप्पणियां:

i. डीपीई ने सीसीईए नोट पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कीं, जिसमें ओएनजीसी को ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) में 10501 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करने की अनुमति दी गई थी।

ii. डीपीई ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचएचआरएल), एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के एक संयुक्त उद्यम के लिए संशोधित इक्विटी निवेश और लागत के संशोधन पर पीआईबी नोट पर अपनी टिप्पणियां दीं।

iii. डीपीई ने 286 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ तमिलनाडु में एचएएल के कार्बन फाइबर संयंत्र पर 635 करोड़ रुपये की परियोजना स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा परिचालित पीआईबी नोट पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कीं।

5. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:

i. वर्ष 2024-25 (मई, 2024 तक) के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा एमएसई से खरीद अनिवार्य 25% (एमएसएमई-संबंध पोर्टल के अनुसार रिपोर्ट किए गए 40 सीपीएसईज़) के मुकाबले लगभग 46.3% थी।

ii. मई, 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25) तक जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद 76,349 करोड़ रुपये थी, जबकि मई, 2023 (वित्तीय वर्ष 2023-24) तक यह 16,393 करोड़ रुपये थी।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

i. शीर्ष 30 सीएसआर व्यय करने वाले सीपीएसईज़ ने वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024 तक) के दौरान लगभग 3,765 करोड़ रुपये के सीएसआर व्यय की सूचना दी है।

ii. पहचान किए गए सीएसआर उप-विषयों पर सीपीएसईज़ के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के चुनिंदा आकांक्षी जिलों (एडी) के मानचित्रण को अंतिम रूप दिया गया और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित आकांक्षी जिलों, सीपीएसईज़, क्षेत्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को सूचित किया गया।

7. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 174 मामले दर्ज/पंजीकृत किए गए। 15 मामलों को वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर खारिज कर दिया गया। 41 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 67 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समितियों के पास हैं। शेष 51 मामले जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं।

*****